मछली पालन के लिए कुवैत के साथ एमओयू

सीएम ने कहा, एग्रीमेंट नया इतिहास रचेगा

7430 करोड़ रुपए का होगा निवेश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाता की समृद्धि के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से किसान कल्याण वर्ष में प्रदेश में पशुपालन, मत्स्य पालन जैसी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित या बढ़ावा दिया जा रहा है.

प्रदेश में तालाबों और जलाशयों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. आज कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच हुआ एग्रीमेंट प्रदेश में मत्स्य पालन और मछुआ कल्याण के क्षेत्र में नया इतिहास रचेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी- ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच, प्रदेश में 7 हजार 430 करोड़ रुपए के निवेश और बाय बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए. यह एग्रीमेंट मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में एग्रीमेंट पर हुए हस्ताक्षर के बाद यह विचार व्यक्त किए. इस अवसर पर मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पंवार, विधायक रामेश्वर शर्मा तथा कुवैत फिश ट्रेड यूनियन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष फारेस बौकम्मा उपस्थित थे.

1 लाख 23 हजार टन वेजिटेबल्स का होगा उत्पादन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में हुए एग्रीमेंट के दौरान जानकारी दी गई कि मप्र एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति-2026 के तहत राज्य में आधुनिक निर्यातोन्मुखी एवं मूल्य संवर्धन मत्स्य उद्योग के विकास के लिए निजी एवं विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रावधान है. अनुबंध के तहत 7 हजार 430 करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश से इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर सहित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा. केज कल्चर के जरिये लगभग 4 लाख टन का अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन अपेक्षित है. इसके साथ ही एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस से 1 लाख 23 हजार टन वेजिटेबल्स आदि का भी उत्पादन होगा. प्रदेश में हो रही इस नई पहल से 15 हजार प्रत्यक्ष और 20 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे. प्रदेश से लगभग 6 हजार करोड़ रुपए के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य है. राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश के मछुआरे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे.

लॉरेंस गैंग का हथियार नेटवर्क खंगाल रही क्राइम ब्रांच

- इंदौर, खरगोन, रतलाम कनेक्शन की पड़ताल तेज

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के दो बिल्डरों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले की जांच अब मध्यप्रदेश में फैले हथियार सप्लाई नेटवर्क तक पहुंच गई है. क्राइम ब्रांच सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गैंग के गुर्गे कसरावद के एक सिकलीगर से देसी पिस्टल खरीदते ही नहीं थे, बल्कि खराब होने पर वहीं उन्हें सुधारने भी ले जाते थे. जांच जब उस सिकलीगर तक पहुंची तो पता चला कि वह खरगोन के चर्चित कॉटन व्यापारी फायरिंग कांड में सरकारी गवाह बन चुका है. अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. क्राइम ब्रांच ने हाल ही में रंगदारी मामले में गिरफ्तार गैंग के गुर्गों को एक साथ रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी राजपाल चंद्रावत और कुलदीप कई बार कसरावद के उस सिकलीगर के संपर्क में रहे, जहां से हथियारों की खरीदी और मरम्मत कराई जाती थी. इसके बाद जब जांच टीम वहां पहुंची तो जानकारी मिली कि संबंधित सिकलीगर पहले से खरगोन पुलिस की जांच में शामिल है और कॉटन व्यापारी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में उसे सरकारी गवाह बनाया जा चुका है. जांच में एक और अहम कड़ी रतलाम का एक माली सामने आया है. सूत्रों का कहना है कि इसी व्यक्ति ने गैंग के गुर्गों की सिकलीगर से पहचान कराई थी. यही माली खरगोन के गोलीकांड में आरोपी है और इंदौर के रंगदारी मामले में भी उसकी भूमिका सामने आने के बाद उसकी तलाश तेज कर दी गई है, फिलहाल वह फरार है. क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क के जरिए गैंग तक हथियार किस तरह पहुंच रहे थे और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ पूरे हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है.

जांच आगे बढ़ाई जा रही है...

आरोपियों की पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. फरार आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और कार्रवाई की जाएगी.

- राजेश दंडोतिया, एडीसीपी

दतिया में 291 मतदान केंद्रों में होगा मतदान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 जुलाई. दतिया विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 2 लाख 20 हजार 371 मतदाता हैं. इसमें पुरुष मतदाता 1 लाख 16 हजार 101, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 4 हजार 260 हैं. मतदान केंद्रों की संख्या 291 हैं.

यह जानकारी सोमवार को निर्वाचन सदन भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने दी. उन्होंने बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान 257 मतदान केंद्र थे. इस बीच विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान 34 नए मतदान केंद्र बनाएं गए हैं.

पेज एक के शेष

भोपाल बनेगा इंडस्ट्री हब

की पहचान बनेगा. अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे. भोपाल औद्योगिक नगरी के रूप में नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. यहां से प्रदेश के विकास का नया सूर्योदय हो रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में जनवरी से लेकर अब तक निवेशकों के साथ 86 हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं. प्रदेशभर में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. प्रदेश की बहनों को भी हर महीने सौगात मिल रही है, अब तक मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना में राज्य सरकार 50 हजार करोड़ से अधिक राशि लाड़ली बहनों को जारी कर चुकी है. बहनें रोजगार आधारित उद्योगों में काम करेंगी तो उन्हें 5000 रुपए अलग से मिलेगा. प्रदेश में विरासत से विकास का कारवां जारी है. हमारे सभी देवस्थान अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. राज्य सरकार रामराज्य की प्रेरणा से हर वर्ग के लिए रोजगार, भोजन और आवास सहित सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है।

इसी माह आएगा यूसीसी

आएगा. उन्होंने कहा कि हिंदू भाई एक शादी करता और सात फेरे लेता है, सभी के लिए एक की कानून होना चाहिए. कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती है, वह बाद में फिर दावा करेगी कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को ये बात याद रखना चाहिए कि समान नागरिक संहिता हर हाल में प्रदेश में लागू की जाएगी. इसके लिए प्रदेश की जनता से राय ली गई है. 10 लाख से अधिक लोगों ने सुझाव दिया है. हम चाहते तो सीधे विधानसभा में बिल ला सकते थे, लेकिन हम जनता की राय के आधार पर फैसला कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश - एक विधान - एक निशान - एक प्रधान की बात कही थी. उनके इस संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार इसी माह यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

एसआईआर और जनगणना दल को मानदेय के भुगतान का इंतजार

- मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में मतदाता सूची पुनरीक्षण पूर्ण
- एसडीएम प्रशिक्षण के लिए दिल्ली रवाना
- नए मतदाता जुड़े और अपात्र नाम हटे

नवभारत न्यूज

उज्जैन. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है. जिले में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। अब कर्मचारियों का भुगतान मिलना बाकी है.

इस व्यापक अभियान के अंतर्गत उज्जैन जिले की सातों तहसीलों उज्जैन, बड़नगर, महिदपुर, तराना, घट्टिया, खाचरौद और नागदा में मतदाता सूची का गहन सत्यापन, नए मतदाताओं का पंजीयन, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन तथा त्रुटियों का निराकरण किया गया.

दिल्ली ट्रेनिंग पर गए एसडीएम

जिले में एसआईआर प्रक्रिया के सफल संचालन के बाद अब निर्वाचन अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण का अवसर भी मिल रहा है. उज्जैन के एसडीएम एल.एन. गर्ग का चयन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विशेष बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किया गया है. इस प्रशिक्षण में देशभर के निर्वाचन अधिकारियों को आधुनिक निर्वाचन प्रबंधन, डिजिटल सत्यापन प्रणाली तथा आगामी चुनावों की तैयारियों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी. माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण का लाभ भविष्य में होने वाले विधानसभा, नगरीय निकाय और अन्य चुनावों के संचालन में मिलेगा.

तपती गर्मी में घर-घर पहुंचे कर्मचारी -एसआईआर प्रक्रिया और जनगणना कार्य के दौरान जिले भर में बूथ स्तरीय अधिकारियों, शिक्षकों, महिला एवं पुरुष कर्मचारियों तथा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों ने तपती गर्मी और विपरीत परिस्थितियों में घर-घर पहुंचकर सत्यापन कार्य किया. इस दौरान हजारों मतदाताओं के नामों का सत्यापन किया गया, पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए तथा अपात्र और दोहरे नामों को सूची से हटाया गया. निर्वाचन विभाग के अनुसार इस प्रक्रिया के बाद जिले की मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने का प्रयास किया गया है.

भुगतान तक नहीं हो पाया - दूसरी ओर, एसआईआर प्रक्रिया और जनगणना संबंधी कार्यों में लगे महिला एवं पुरुष अधिकारी-कर्मचारियों को अब तक उनके अतिरिक्त कार्य का मानदेय प्राप्त नहीं हो पाया है. कर्मचारियों ने निर्धारित कार्यालयीन समय के अतिरिक्त ओवरटाइम कार्य करते हुए कई दिनों तक फील्ड में रहकर जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था. इसके बावजूद अब तक मानदेय राशि का भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा देखी जा रही है.

नया काम थोपने की तैयारी

निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों का कहना है कि शासन स्तर से अतिरिक्त कार्य के लिए मानदेय दिए जाने की बात कही गई थी, बावजूद अभी तक भुगतान नहीं हो सका है. जबकि आने वाले समय में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं, सर्वेक्षणों और अन्य प्रशासनिक कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी इन्हीं कर्मचारियों को सौंपी जानी हैं. ऐसे में कर्मचारियों को उनके लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाना आवश्यक है, ताकि वे आगामी दायित्वों का निर्वहन भी पूरी क्षमता और उत्साह के साथ कर सकें.

पारदर्शी होगी प्रक्रिया -जिले में एसआईआर प्रक्रिया के पूर्ण होने के साथ ही निर्वाचन विभाग आगामी चुनावी तैयारियों की दिशा में आगे बढ़ चुका है. प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि मतदाता सूची के अद्यतन होने और अधिकारियों के उन्नत प्रशिक्षण से भविष्य की निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित तथा तकनीकी रूप से सुदृढ़ होगी.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60